एच-1बी शुल्क बढ़ोतरी से अमेरिका को नुकसान

भारतीय आईटी कंपनियों को ऑफशोरिंग से मिलेगा फायदा

ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा शुल्क 1 लाख डॉलर किया

नई दिल्ली, 21 सितंबर एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाकर प्रति कर्मचारी 1,00,000 अमेरिकी डॉलर करने का फैसला भारत की तुलना में अमेरिका के लिए अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है.

जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय आईटी कंपनियाँ पहले से ही अमेरिका में 50-80 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं. उनका मानना है कि इस कदम से अमेरिका में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ऑन-साइट भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करना स्थानीय कर्मचारियों की तुलना में अधिक महंगा हो जाएगा.

ऑफशोरिंग को बढ़ावा- जीटीआरआई ने कहा, इस भारी शुल्क के चलते कंपनियाँ ऑफशोरिंग को बढ़ावा देंगी, जिससे भारत से ही रिमोट वर्क में वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि एच-1बी वीज़ा के लिए आवेदन कम होंगे, स्थानीय स्तर पर कम भर्तियाँ होंगी, और अमेरिकी ग्राहकों के लिए परियोजना की लागत बढ़ेगी. अंततः, इससे नवाचार की गति भी धीमी होगी. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत को इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए. देश को लौटने वाले प्रतिभाशाली पेशेवरों का उपयोग सॉफ्टवेयर, क्लाउड और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी घरेलू क्षमता को मजबूत करने के लिए करना चाहिए. इस तरह, अमेरिका के इस संरक्षणवादी कदम को भारत के डिजिटल %स्वराज मिशन के लिए एक दीर्घकालिक लाभ में बदला जा सकता है.

नए आवेदकों पर शुल्क- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 सितंबर को एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया था. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 1,00,000 डॉलर का यह नया शुल्क केवल उन कंपनियों पर लागू होगा जो नए आवेदकों को अमेरिका में रोजगार देना चाहती हैं.

अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी

विश्लेषकों का मानना है कि इस नीति से अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी और उनकी परियोजनाओं की कार्यक्षमता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. वहीं, भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने डिजिटल कौशल और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक आईटी बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करे.

रेडिसन होटल समूह पूर्वी भारत में विस्तार करेगा

बेंगलुरु, 21 सितंबर. रैडिसन होटल ग्रुप अब देश के पूर्वी हिस्से में भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आतिथ्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का ध्यान बड़े और छोटे दोनों शहरों में संपत्तियों की संख्या को संतुलित करने पर है. समूह के दक्षिण एशिया परिचालन के चेयरमैन के बी काचरू ने कहा कि पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को तोड़कर उनकी जगह आधुनिक इमारतें बनाने के बजाय, उन्हें धरोहर संपत्तियों के रूप में पुनर्स्थापित और संरक्षित किया जाना चाहिए. काचरू ने बताया, हमारी तरक्की का एक कारण यह है कि हम पूरे भारत में महत्वपूर्ण जगहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. वास्तव में, हम बड़े शहरों की तरह ही छोटे और मझोले शहरों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

हिंद महासागर में खनिज खोज को नई गति

पॉलीमेटेलिक सल्फाइड खनिजों का होगा अन्वेषण

आईएसए के साथ दो अनुबंध पाने वाला पहला देश

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता) भारत ने हिंद महासागर के नीचे कार्ल्सबर्ग घाट क्षेत्र के 10 हजार वर्ग किलो मीटर के हिस्से में खनिजों के अन्वेषण का अधिकार हासिल किया है जिससे गहरे समुद्र के नीचे खनिजों के अन्वेषण और निकासी के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को बल मिला है.

पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के बीच एक नए 15-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर की शुक्रवार को जानकारी दी. इसके तहत भारत को कार्ल्सबर्ग घाट क्षेत्र के उस 10 हजार वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण का विशिष्ट अधिकार होगा. पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लैटिनम जैसी मूल्यवान धातुएँ होती हैं. पीएमएस समुद्र तल की कठोर परत से निकलने वाले गर्म जलतापीय तरल पदार्थों द्वारा निर्मित एक प्रकार के अवक्षेप होते हैं. इनकी रणनीतिक और व्यावसायिक क्षमता ने देशों का ध्यान आकर्षित किया है. अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समुद्र के नीचे तीन लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत में फैला कार्ल्सबर्ग घाट क्षेत्र पॉलीमेटेलिक सल्फाइड खनिज की संभावनाओं वाला क्षेत्र है.

इस तरह भारत आईएएस के साथ दो पीएमएस अन्वेषण अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश बना गया है और देश को एक अग्रणी निवेशक के रूप में मान्यता मिली है.

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए गहरे समुद्री मिशन के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समुद्र तल खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की ब्लू इकोनॉमी पहल को मजबूत करने पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, 卐कार्ल्सबर्ग घाट में पीएमएस अन्वेषण के अनन्य अधिकारों को औपचारिक रूप देकर, भारत ने गहरे समुद्र में अनुसंधान और अन्वेषण में अपनी अग्रणी स्थिति को और मज़बूत किया है. इससे हमारी समुद्री उपस्थिति बढ़ेगी और भविष्य में संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण होगा.

सोना-चांदी की तेजी पर लगा ब्रेक

24 कैरेट सोना रुपये 68 बढ़कर 1,09,775 पर

नई दिल्ली, 21 सितंबर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी पर अब ब्रेक लगता नजर आ रहा है. बीते हफ्ते दोनों कीमती धातुओं के दाम एक सीमित दायरे में रहे, क्योंकि फेडरल रिजर्व के फैसले का शुरुआती असर खत्म हो गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत मामूली रूप से 68 रुपये बढ़कर 1,09,775 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जो एक हफ्ते पहले 1,09,707 रुपये थी. इसी तरह, 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,00,554 रुपये और 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 82,331 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आई है. यह 8 रुपये कम होकर 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि एक हफ्ते पहले यह 1,28,008 रुपये प्रति किलोग्राम थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में, शुक्रवार को अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 572 रुपये के उछाल के साथ 1,09,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. इसी तरह, दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 1,668 रुपये बढ़कर 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था, जो अब एक सीमित दायरे में आ गया है.

पीएलआई योजना से 12 लाख नौकरियां बनीं

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2.13 से 5.25 लाख करोड़ पहुँचा

ऑटो सेक्टर में 67,000 करोड़ से अधिक निवेश आया

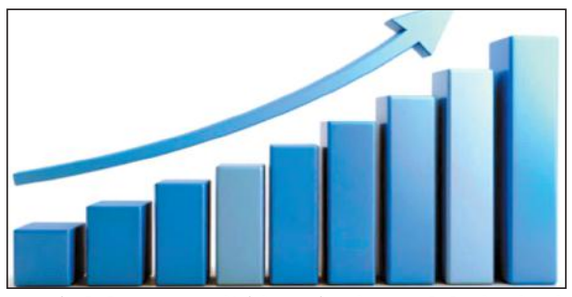

नई दिल्ली, 21 सितंबर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने देश में विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा दी है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता दिख रहा है.

पीएलआई योजना की शुरुआत मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों से हुई थी. धीरे-धीरे इसका विस्तार ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और सेमीकंडक्टर जैसे 14 रणनीतिक क्षेत्रों तक किया गया है. अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जो इस योजना की व्यापकता को दर्शाता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर का शानदार प्रदर्शन- इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र ने विशेष रूप से शानदार प्रदर्शन किया है. इस क्षेत्र का उत्पादन 2020-21 में 2.13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 5.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसी तरह, ऑटो और ऑटो-कंपोनेंट्स उद्योग में भी 67,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोमोटिव सप्लाई चेन को मजबूती मिली है.

16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल बिक्री

पीएलआई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के प्रतिभागियों की संयुक्त बिक्री मार्च 2025 तक 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है. यह आंकड़ा भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता का प्रमाण है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अभी इस योजना का सीधा और सीमित लाभ ही मिल रहा है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को आने वाले बजट (2025-26) में पीएलआई के लिए अधिक फंड आवंटित करना चाहिए और इसकी निगरानी प्रणाली में सुधार लाना चाहिए.

बाजार पर दिखेगा वीजा शुल्क का दबाव

आईटी कंपनियों पर अगले हफ्ते दबाव संभावित

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में जोरदार तेजी

मुंबई, 21 सितंबर (वार्ता) घरेलू शेयर बाजारों में तीन सप्ताह की तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में एच-1बी वीजा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि का असर दिखाई देगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा शुल्क में कई गुना वृद्धि कर इसे एक लाख डॉलर कर दिया है. इसके अलावा निवेशकों की नजर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में हुई प्रगति पर होगी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसी सिलसिले में सोमवार को अमेरिका जा रहे हैं. आने वाले सप्ताह में आईटी कंपनियों पर वीजा शुल्क का दबाव रह सकता है.

गत सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 721.53 अंक (0.88 प्रतिशत) की बढ़त में 82,626.23 अंक पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 213.05 अंक यानी 0.85 अंक की साप्ताहिक तेजी में सप्ताहांत पर 25,327.05 अंक पर बंद हुआ.

मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने ज्यादा विश्वास जताया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 1.24 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 में 2.86 प्रतिशत की तेजी रही.

चावल-गेहूं महंगे, चीनी भाव गिरे

नई दिल्ली, 21 सितंबर बीते सप्ताह घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल और गेहूं के औसत भाव में मजबूती देखी गई, जबकि खाद्य तेलों और दालों में मिला-जुला रुख रहा. चीनी के भाव नरम रहे.

अनाज- सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत रु. 83 बढ़कर रु. 3,842.74 प्रति क्विंटल हो गई, जबकि गेहूं रु. 4 महंगा होकर रु. 2,863.02 प्रति क्विंटल के भाव बिका. वहीं, आटे की कीमत में 11 की गिरावट आई.

खाद्य तेल- सरसों, मूंगफली और पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सूरजमुखी और सोया तेल महंगे हुए. वनस्पति के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ.

दाल-दलहन- उड़द, चना और मूंग दाल की औसत कीमतों में साप्ताहिक तेजी रही, जबकि तुअर और मसूर दाल सस्ती हुई.

गुड़-चीनी- मीठे के बाजार में गुड़ के औसत भाव में ?35 की वृद्धि हुई, वहीं चीनी में ?13 प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई.

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू

छोटे व्यापारियों को लाभ, उपभोक्ताओं को राहत

कीमतों में 15-20 प्रतिशत तक कमी

नई दिल्ली, 21 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इन सुधारों की सराहना करते हुए कहा है कि ये कदम छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाएंगे, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेंगे.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को बताया कि इन सुधारों के तहत लगभग 400 वस्तुओं को 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के कर स्लैब से हटाकर पांच प्रतिशत के स्लैब में लाया गया है. साथ ही, 28 प्रतिशत के कर स्लैब को खत्म कर अधिकांश वस्तुओं को 18 प्रतिशत के स्लैब में शामिल किया गया है.

एक मोटे अनुमान के अनुसार, इस साहसिक निर्णय से वस्तुओं की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा. इससे उपभोग बढ़ेगा और व्यापार में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी. खंडेलवाल ने देशभर के व्यापारी संगठनों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कीमतों में कमी का लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुँचे.

समाचार विशेष

बिहार में सीट शेयरिंग पर मामला गरम!

पटना. बिहार में चुनावी लहर है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है! सीट बंटवारे को लेकर चल रहे इस विवाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इधर, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) सुप्रीमो जीतन राम मांझी कम से कम 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं.

मांझी ने भाजपा और जदयू के नेताओं से यहां तक ??कह दिया है कि वह 15 सीटों की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके लिए करो या मरो की स्थिति है. मांझी ने सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ाते हुए यह भी कहा कि अगर उनकी मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिलीं, तो आगामी बिहार चुनाव में 'हम' पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

'हम' के संरक्षक जीतन राम मांझी ने को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह एनडीए में अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं. इस मांग के पीछे पार्टी की मान्यता मुख्य कारण है. 'हम' पार्टी पिछले 10 सालों से एक पंजीकृत पार्टी है, अभी तक इसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता नहीं मिली है. मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 7-8 विधायक या 6 प्रतिशत वोट होना ज़रूरी है.

एनडीए नेताओं से मांझी ने की विनती- मांझी ने एनडीए नेताओं से कहा कि कम से कम 'हम' पार्टी को इतनी सीटें तो देनी चाहिए कि उसे बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिल जाए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह एनडीए नेताओं से अपनी पार्टी की मान्यता के लिए विनती कर रहे हैं, इन सीटों पर उनका कोई दावा नहीं है.

2020 में 'हम' को मिली थी 7 सीटें

गौरतलब है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन करके 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. इनमें से मांझी की पार्टी ने 4 सीटें जीती थीं. पार्टी को 0.89 प्रतिशत वोट मिले थे. जीतन राम मांझी 2024 में गया से लोकसभा सांसद चुने गए और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं. हालांकि, उनकी पार्टी अभी तक बिहार में 6 प्रतिशत वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है. दरअसल, चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद किसी राजनीतिक दल को कई सुविधाएं मिलती हैं.

कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी से बने चार-चार विधायक

यहां भाजपा के लिए अब तक दरवाजा बंद

बेगूसराय. चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद रोचक इतिहास रखता है. अपने समय में राजनीति समीकरण को प्रभावित करने की हैसियत रखने वाले सोशलिस्ट स्व. राम नारायण चौधरी, कांग्रेसी स्व. हरिहर महतो, कम्युनिस्ट स्व. सुखदेव महतो व समाजवादी रामजीवन सिंह यहां से विधायक रहे हैं.

वर्ष 1952 से लेकर 2020 तक हुए चुनावों में यहां जनता ने कांग्रेस, सोशलिस्ट, जनता दल, राजद, लोजपा, जदयू और कम्युनिस्ट तक को मौका दिया, लेकिन अबतक भाजपा को जनता ने यहां से प्रवेश नहीं करने दिया. क्योंकि पहले भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाए. इधर,

तीन बार से विधानसभा सीट भी सहयोगी दल के कोटे में जा रही है.

इस क्षेत्र से जीते स्व. हरिहर महतो, रामजीवन सिंह, अशोक महतो और कुमारी मंजू वर्मा मंत्री पद तक पहुंचे. बेगूसराय जिले में सबसे ज्यादा मंत्री पद देने का रिकार्ड भी चेरिया बरियारपुर के नाम है. रामजीवन सिंह ने पांच बार और हरिहर महतो ने चार बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. पहले चुनाव 1952 में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के रामनारायण चौधरी ने कांग्रेस नेता हरिहर महतो को हराकर इतिहास रचा. लेकिन 1957 और 1962 में हरिहर महतो ने वापसी कर जीत दर्ज की. इसके बाद 1967, 69 और 1972 में रामजीवन सिंह ने लगातार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई. जेपी लहर के बावजूद 1977 में हरिहर महतो ने कांग्रेस का परचम लहरा वापसी की. 1980 में सीपीआइ नेता स्व. सुखदेव महतो विजयी हुए, लेकिन 1985 में हरिहर महतो ने पुन: कब्जा जमाया.

अबकी बार भाजपा की नजर

इतिहास गवाह है कि यह सीट कभी एकतरफा नहीं रही. हर चुनाव में कांटे का मुकाबला और अप्रत्याशित उलटफेर होता रहा है. 2025 के चुनाव को देखते हुए भाजपा के नेता-कार्यकर्ता पटना से लेकर दिल्ली तक पूरी ताकत लगा रहे हैं, ताकि पहली बार इस क्षेत्र को भगवा रंग मिल सके. वहीं लोजपा और जदयू भी अपनी-अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं.

सिद्धारमैया से नाराज हैं लिंगायत

बेंगलुरु. कर्नाटक में जातीय गणना शुरू होने वाली है. उससे पहले घमासान शुरू हो गया है. राज्य के सबसे बड़े जातीय समूह लिंगायत मुख्यमंत्री से नाराज है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं.

भाजपा भी इससे नाराज है. यह भी कहा जा रहा है कि उप समूहों में बांटने की कोशिश हो रही है, इससे उनकी संख्या कम दिखेगी. अभी लिंगायत कर्नाटक की करीब सात करोड़ की आबादी में अपने को एक चौथाई से ज्यादा बताते हैं. हालांकि कर्नाटक सरकार की पिछली जातीय गणना में उनकी आबादी सिर्फ 66.35 लाख यानी 11 फीसदी बताई गई थी. इससे लिंगायत समुदाय काफी नाराज है. बहरहाल, 22 सितंबर से शुरू होने वाली जातीय गणना से पहले लिंगायत समुदायों में विभाजन दिखने भी लगा है. वीरशैव लिंगायत एकता समावेश ने शुक्रवार को हुबली में एक सम्मेलन का आयोजन किया है. कहा जा रहा है कि जागतिक लिंगायत महासभा के लोग इससे दूर रहेंगे. वीरशैव लिंगायत समुदाय ने लोगों से अपील की है कि धर्म के लिए बने कॉलम में 'अन्य' श्रेणी में अपने को दर्ज करें और वीरशैव लिंगायत के रूप में ही दर्ज करें.

विशेष | **पीके का किला उखाड़ अभियान क्या गुल खिलाएगा?**

प्रशांत किशोर की 1200 परिवारों के वर्चस्व को चुनौती

पटना. बिहार की सियासत में इन दिनों प्रशांत किशोर का नाम खूब चर्चा में है. पीके ने हर पार्टी और उसके नेता खिलाफ 'किला उखाड़' अभियान छेड़ रखा है. पीके के तरकश से अब एक नया तीर निकला है. पीके ने दावा किया है कि बिहार की राजनीति पर सिर्फ '1200 परिवारों' का ही कब्जा है. यही 1200 परिवारों के बेटा-बेटी, नाना-नानी और चाचा-चाची और बहन-भाई चुनाव लड़ते हैं और जीतते आ रहे हैं.

प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की राजनीतिक गलियारों में अब एक नई बहस छेड़ दी है. पीके ने कहा है कि वह रणनीति बना रहे हैं कि इन 1200 परिवारों को राजनीति से कैसे उखाड़ा जाए. पीके ने कहा कि उनका मकसद इन्हीं परिवारों की पकड़ को खत्म करना है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पीके किस रणनीति के तहत इन परिवारों की राजनीति से बिहार को 2025 में मुक्त कराएंगे? प्रशांत किशोर की यह रणनीति 2025 के चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी?

प्रशांत किशोर की राजनीति पारंपरिक दलों से काफी अलग है. वह न तो किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और न ही खुद को तुरंत चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं. उनकी रणनीति एक 'लॉन्ग टर्म' प्रोजेक्ट पर आधारित है. पीके बिहार में गांव-गांव जाकर पदयात्रा कर अब सुबह से लेकर देर रात तक बैठकें करते रहते हैं. बिहार को बदलने की तमन्ना है और वह लोगों से अपने खातिर नहीं तो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर वोट देने की बात कर रहे हैं.

'जन सुराज' रणनीति बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय

प्रशांत किशोर का यह कदम सीधे तौर पर दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों- एनडीए और महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है. पीके का यह बयान सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला है. आरजेडी की राजनीति में परिवारवाद का इतिहास रहा है और पीके का यह बयान उनकी कमजोर नस पर चोट कर सकता है. अगर पीके अपने जनाधार को मजबूत करते हैं तो वह महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, जिससे तेजस्वी यादव के लिए राह मुश्किल हो सकती है. वहीं, प्रशांत किशोर एनडीए के लिए भी खतरा हैं. अगर लोग वर्तमान सरकार से नाखुश हैं, लेकिन वे आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते तो पीके का 'जन सुराज' उनके लिए एक विकल्प बन सकता है. इससे एनडीए का वोट बैंक भी बंट सकता है और उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है. प्रशांत किशोर की 'जन सुराज' रणनीति बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय है. यह एक जोखिम भरी रणनीति है, क्योंकि यह पारंपरिक राजनीतिक दलों की मजबूत मशीनरी के खिलाफ खड़ी है. लेकिन अगर पीके अपने मकसद में कामयाब होते हैं, तो वह बिहार में दशकों से चले आ रहे परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर सकते हैं.